(ख) क्या कीटनाशी दवा तैयार करने के लिए कंजड़/नीम जैसे वृक्षों पर कोई प्रयोग किये गये हैं; और यदि हां, तो इन वृक्षों से कितनी कीटनाशी दवा तैयार की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) फसलों को होने वाली हानि को कम करने के लिए कीट नियंत्रण की सांस्कृतिक, यांत्रिक, जीववैज्ञानिक और रासायनिक विधियों युक्त व्यापक उपाय पैकेज को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने उड़ने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तथा करंज सहित पौध निष्कर्षों पर प्रयोग किए हैं । नीम आधारित चार कीटनाशियों के निरूपण व्यापारिक उपयोग के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत किए गए हैं ।

कृषि विज्ञान क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये रिक्त पद

546. **श्रीह राम सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) का यह सच है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक पद खाली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों का ब्यौरा क्या है और किन-किन केन्द्रों में ये पद खाली हैं; और

(ग) सरकार ने अपने स्तर पर इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठत

शुष्क भूमि खती

547. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शुष्क भूमि खेती के सम्बन्ध में एक नई परियोजना की रूपरेखा तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री

(श्री अरविंद नेताम) (क) से (ग) जी,हां । पुनर्गठित राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना निम्नलिखित बातों पर बिशेष ध्यान देते हुए देश में बायोमास के सतत उत्पादन तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों के वृहत स्थानों पर पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास करेगी ;

(1) भूमि, जल, वनस्पति, प्राणी तथा मानव संसाधनों जैसे प्रकृति प्रदत्त स्रोतों का एक समान तथा एकीकृत रूप में संरक्षण, उन्नयन तथा उपयोग । इसका उद्देश्य विविध प्रकार के भू-उपयोग के माध्यम से मनुष्य तथा पशुधन संख्या की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भोजन, चारे, ईंधन, रेशे, लकड़ी तथा बायोमास की निरंतर उपलब्धि सुनिश्चित करना है ।

(2) भोजन, ईंधन तथा चारे के अतिरिक्त, इस परियोजना का उद्देश्य आकस्मिक रोजगार बढ़ाने, कृषि तथा डेरी उत्पाद का विपणन अधिशेष, उपयुक्त क्षेत्रों में सब्जियों, धनियां, जीरा, चिकित्सीय महत्व के पौधों आदि के माध्यम से वर्षासिंचित क्षेत्रों के कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की नकद आमदनी में वृद्धि करना है ।

(3) भूमि वर्षा-जल के वैज्ञानक प्रबंध के माध्यम से उत्पादन पर्यावरण में सुधार तथा पारिस्थितिक संतुलन का पुनःस्थापन

स्थान पर नमी संरक्षण वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालियों की शुरूआत वर्षा के बहते पानी को रोकने के लिए अवरोध प्रबंध तथा भूमिगत जलभण्डार में वृद्धि करने के साधनों के माध्यम से मनुष्यों तथा पशुधन के लिए पेयजल घरेलू खपत के लिए जल की अधिक उपलब्धता, जीवन रक्षक सिंचाई तथा कृषि मौसमीय क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त नकदी फसलों की खेती सुनिश्चित की जाएगी ।

प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए पनधारा के तीनों स्थान सबद्ध घटकों, नामतः, कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि तथा निकास मार्गों का एक अंगीय भूजल वैज्ञानिक अस्तित्व के रूप में शोधन किया जाएगा ।

वर्षासिंचित क्षेत्र परियोजना 1990–91 से सभी राज्यों तथा दो केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । देश के 30 प्रतिशत से कम कृष्य भूमि तथा सुनिश्चित सिंचाई सुविधा वाले सभी सामुदायिक विकास खंड इस परियोजना में सम्मिलित होने के पात्र होंगे । चुने गए विकासखंडों में से प्रत्येक में 500 से 5000 हैक्टेयर की लघु पनधारा का विकास सतत फार्मिंग प्रणाली के माडल के रूप में किया जाएगा ।

इस नीति के अनुसरण में सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों को 1990–91 से अब तक 317.418 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं ।

Cultivation of Hops in Hilly Areas

548. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Horticulture Board proposed a comprehensive scheme for the cultivation of hops in hilly areas;

(b) if so, the details therof;

(c) whether any hilly areas of Andhra Pradesh are identified for the cultivation of hops by National Horticulture Board; and

(d) whether any proposals for pilot projects are under Government's consideration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b): The National Horticulture Board has no comprehensive scheme for cultivation of hops in hilly areas. However, the Board has approved a proposal recommended by the Government of Himachal Pradesh for development of 50 ha. land under hops and for strengthening hops processing at a total cost of Rs. 51.335 lakh.

(c) and (d): No, Sir.

Formulation of National Seeds Policy

549. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate a National Seeds Policy;

(b) if so, the details therof;

(c) whether it is a fact that some of the multinationals in the seed industry have been exploiting the farmers by charging exhorbitant prices; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b): No, Sir. Question does not arise.

(c) and (d): Seed prices are not being statutorily regulated. Seed producing agencies fix seed prices based on their costs of production and commercial judgement.